

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3358

(जिसका उत्तर सोमवार, 09 अगस्त, 2021/18 श्रावण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

“जीएसटी के अंतर्गत आईटीईएस की आपूर्ति”

†3358. डॉ. डी.एन.वी. सेंथिलकुमार एस.:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित संदेहों को स्पष्ट करने के लिए, 20.09.2019 को आयोजित अपनी 37वीं बैठक के दौरान माल और सेवा कर (जीएसटी) परिषद द्वारा अनुमोदित संशोधित परिपत्र जारी करेगी क्योंकि इस तरह के स्पष्टीकरण के अभाव में, जीएसटी अधिकारियों द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं को जीएसटी के तहत मध्यस्थ सेवाओं के रूप में मानने की व्याख्या से 38 बिलियन अमेरिकी डालर के उद्योग की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): जीएसटी परिषद ने दिनांक 20.09.2019 को हुई अपनी 37वीं बैठक में एक परिपत्र को जारी करने के लिए अपना अनुमोदन दिया था जिससे कि परिपत्र सं. 107/26/2019-जीएसटी, दिनांक 18.07.2019 को जारी किए जाने के परिणामस्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं की आपूर्ति के बारे में पैदा होने वाले संदेहों को दूर किया जा सके। हालांकि जीएसटी परिषद की जीएसटी क्रियान्वयन समिति (जीआईसी) ने दिनांक 02.12.2019 को हुई अपनी 34वीं बैठक में इस मुद्दे पर और आगे विचार किया और अन्य बातों के अलावा यह सिफारिश की है, कि:-

- (i) अभिव्यक्ति “मध्यस्थ” से संबंधित नीतिगत मुद्दों के बारे में निर्णय सबसे पहले लिया जाना चाहिए;
- (ii) जीएसटी परिषद के अनुमोदन से विधिक आशय को स्पष्ट करने के उद्देश्य से कानून में यथोचित परिवर्तन किए जाने के लिए विचार किया जाना चाहिए;
- (iii) परिपत्र सं. 107/26/2019-जीएसटी, दिनांक, 18.07.2019 को निरसित कर दिया जाना चाहिए; और
- (iv) निहित नीतिगत मुद्दों पर बिना आगे विचार किए कोई नया परिपत्र न जारी किया जाए।

जीआईसी के इस निर्णय को जीएसटी परिषद ने दिनांक 18.12.2019 को हुई अपनी 38वीं बैठक में अपने संज्ञान में लिया था। उक्त निर्णय को लागू करने के लिए परिपत्र सं. 127/46/2019-जीएसटी, दिनांक 04.12.2019 को जारी करके परिपत्र सं. 107/26/2019-जीएसटी, दिनांक 18.07.2019 को रद्द कर दिया गया है।
